Review of Research
International Online Multidisciplinary Journal

ISSN 2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume - 5 | Issue -5 | Feb - 2016

''महिलाओं का आर्थिक परिवर्तन : यही समय है''

श्रीमती वर्षा राहुल
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
दयानन्द वैदिक महाविद्यालय उरई, जालौन.

सारांश :–

इस कार्यनीति को तैयार करने में नीति आयोग ने अत्यंत सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। नीति आयोग के प्रत्येक क्षेत्र में हितधारकों के तीनों समूहों यथा कारोबारी व्यक्ति, वैज्ञानिकों सहित शिक्षाविद् और सरकारी अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया।

इसके बाद उपाध्यक्ष के स्तर पर हितधारकों के 7 सेटों में से प्रमुख व्यक्तियों के विविधतापूर्ण समूह के साथ विचार–विमर्श किया गया। इन प्रमुख व्यक्तियों में वैज्ञानिक और नवोन्मेषी , किसान, सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रमिकों के प्रतिनिधि और श्रम संगठन तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रत्येक अध्याय के मसौदे को विचार–विमर्श के लिये वितरित किया गया और जानकारियां , सुक्षाव तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिये केंद्रीय मंत्रियों को भी साथ जोड़ा गया। इसके दस्तावेज का मसौदा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी वितरित किया गया जहां से प्राप्त बहुमूल्य सुक्षावों को इसमें शामिल किया गया।

इस दस्तावेज को तैयार करते समय सरकार के भीतर केंद्रीय राज्य और जिला स्तर पर 800 के ज्यादा हितधारकों और लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया गया।

इस कार्यनीति दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि निजी निवेशक और अन्य हितधारक अभिनव भारत 2022 के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सके और 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सके।

भूमिका :–

नीति आयोग द्वारा अभिनव भारत ⁄75 के लिये कार्यनीति जारी की गई है। जिसके अन्तर्गत अनेक उद्देश्यों को विश्लेषित किया गया है। इसमें 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की एक विस्तृत प्रदर्शनी सम्मिलित है। जिसमें पहले से हो चुकी प्रगति को मान्यता दी गई है और प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं हेतु सुक्षाव भी दिये गये है।

19 दिसम्बर 2018 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ0 राजीव कुमार , सदस्य डॉ0 रमेशचंद्र , डॉ0 वी के सारस्वत और सी.ई.ओं. श्री अमिताभ कांत की उपस्थिति में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा अभिनव भारत ⁄75 की रणनीति का आगाज़ हुआ। नीति आयोग ने 2017 में माननीय प्रधानमंत्री के आवाह्न से प्रेरण और दिशा प्राप्त करते हुए 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना के लिए रणनीति दस्तावेज तैयार करने की यात्रा प्रारंभ की थी।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
2. यह पता करना कि महिलाओं के आर्थिक परिवर्तन का स्तर क्या है।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन बिना कार्यक्रम के नहीं हो सकता।
2. महिलायें समाज का उपेक्षित वर्ग है। इनमें सुधार सरकारी नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने पर निर्भर है।

41 अध्यायों को चार खण्डों में विभाजन :–

नीति आयोग द्वारा इस दस्तावेज़ के 41 अध्यायों को चार खण्डों में विभाजित किया गया है। जो इस प्रकार है– वाहक (Drivers),अवसंरचना (Infrastructure),समावेशन (Inclusion) और गवर्नेंस (Governance)।

वाहक में सम्मिलित अध्याय :–

चार खण्डों में प्रथम खण्ड वाहक के अन्तर्गत आते है, आर्थिक निष्पादन के साधनों, विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अनेक अध्यायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कुछ प्रमुख सिफारिशें है– वर्ष 2023 तक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत तक पहुँचाना जिससे भारत लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जायेगा। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वृद्वि को 36 प्रतिशत तक बढ़ाना भी प्रमुख लक्ष्य है । कृषि क्षेत्र में ई–राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को कृषि उद्यमियों में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए जिस हेतु अधिक उन्नति अंकित की जा सकें ।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना जिससे लागत में कमी आती है। मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है। रोजगार के अधिकतम साधनों का सृजन सुनिश्चित करने के लिये श्रम कानूनों का संहिताकरण करने और प्रशिक्षुताओं को बढ़ाने के प्रबल प्रयास किये जाने चाहिए।

खनन अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति का पुननिर्माण करने के लिये एक्सप्लोर इन इंडिया मिशन का आरंभ करना। आदि।

अवसंरचना में सम्मिलित अध्याय :–

यह भारतीय कारोंबारों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने में और नागरिकों के जीवन की सुगमता को सुनिश्चित करने में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। आर.डी.ए. की स्थापना में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर.डी.ए. रेलवे के लिये एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करेगा।

तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट परिवहन के अंश का दोहरा करना। बुनियाद ढाँचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरूआत में, वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराई जायेगी।

परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने तथा मल्टी–मॉडल और डिजिटाइज़्ड गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिये आई.टी.–सक्षम मंच का विकास।

2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों डिजिटल रूप से जुड़ जायेगी। वर्ष 2022–23 तक सभी सरकारी सेवाएं राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

समावेशन में सम्मिलित अध्याय :–

समावेशन से संबंधित खण्ड समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है। इस खण्ड के तीन विषय स्वास्थ्य, शिक्षा और परंपरागत रूप से हाशिये पर मौजूद आबादी के वर्गों को मुख्य धारा में लाने के आयामों के इर्द–गिर्द घूमते है।

देशभर में 150000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने सहित आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन।

केंद्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये फोकल प्वांइट बनाना। समेकित चिकित्सा पाठयक्रम को प्रोत्साहन देना।

2020 तक कम से कम 10000 अटल टिंकरिंक लैब्स की स्थापना के ज़रिये जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।

प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्ररी की संकल्पना करना। आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को प्रोत्साहन देना।

गवर्नेंस में सम्मिलित अध्याय :–

गवर्नेंस से संबंधित अंतिम खण्ड में इस बात पर गहन चिंतन किया गया है कि विकास के बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये गवर्नेंस के ढाँचों को किस तरह सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है।

उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों जैसे– तर्कसंगतता और सेवाओं में सामंजस्य के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूद 60 से अधिक अलग सिविल सेवाओं को कम करना, सिविल सेवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा को 2022–23 तक सामान्य श्रेणी के लिये 27 साल तक सिमित किया जाना आदि का कार्यान्वयन करना।

मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्वरित बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिये मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आकलन करने के लिये नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना। लंबित मामलों को निपटाना – नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना।

भराव के क्षेत्रों को कवर करने प्लास्टिक अपशिष्ट और नगर निगम के अपशिष्ट तथा अपशिष्ट से धन सृजित करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना।

सभी देशों में महिलायें अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार लैंगिक मजदूरी अंतराल सीधे तौर पर आय असमानता को विश्लेषित करता है। इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये ही सरकार ने अभिनव भारत /75 का शुभारंभ किया। जिसके अर्न्तगत पैनल ने छह मुद्दों को पहचान कर संशोधन हेतु कार्य करने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष :–

इस दस्तावेज़ को शासन की पुनः कल्पना के संदर्भ में तैयार किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत को ऐसी ''डेवलैपमेंट स्टेट'' में पहुँचने की जरूरत है जो प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के मुश्किल और उत्तरदायी वितरण पर केंद्रीय हो। इसके लिये सार्वजनिक निजी साझेदारी के इष्टतम स्तर को हासिल करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है।

वस्तुओं और सेवाओं के अधिक कुशल वित्रन के लिये नीतियों लागू की गई है जैसे स्वास्थ्य , शिक्षा , बिजली , शहरी जल आपूर्ति एंव संयोजकता। इस संदर्भ में उद्यमिता और निजी निवेश को बढ़ावा देकर लालफीताशाही और बोझिल विनियमन को खत्म करने के लिये एक सुचिन्तित प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, ''अभिनव भारत /75 कार्यनीति'' को संयुक्त राष्ट्र के सी.डी.जी. के साथ संरेखित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

यही कारण है कि कार्यनीति के सभी अध्यायों को उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में तैयार किया गया है। वर्तमान में भारत सबका साथ सबका विकास के दर्शन के साथ डेवलेपमेंट स्टेट के रूप में परिणत हो रहा है। 2022–23 में अभिनव इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने और उनमें वृद्वि करने हेतु अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिये।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 21वीं शताब्दी में मौजूद प्रौद्योगिकी के साथ विकास की गति को व्यापक रूप दिया जा सकता है। सभी भारतीयों के संकल्प के साथ भारत को सिद्धि प्राप्त होगी। 75 आजादी के वर्ष

का जश्न मनाते हुए नीति आयोग द्वारा प्रमुख पहल महिला उद्यमिता के लिये किया गया। जिसमें एक महोत्सव का आयोजन होगा और उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया जायेगा।

डब्लू.टी.आई. पुरस्कार नीति आयोग का प्रयास है कि वह भारत में व्याप्त असाधारण महिला परिवर्तन निर्माताओं को पहचान कर उनकी कहानियों को लोगो तक पहुँचाकर प्रेरणा फैलायें। इस हेतु आवेदक स्वंम आवेदन कर 31 दिसंबर 2021 तक वेबसाइड https://web.gov.in में भेज सकता है। इसके अंर्तगत 75 उद्यमि महिलाओं को चयनित कर 08 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जायेगा।

सन्दर्भ सूची

1. योजना, 2021।
2. कुरूक्षेत्र अक्टूबर अंक।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक।
4. यू.पी.यू.ई.ए. इकोनामिक जर्नल पृष्ठ–653।
5. यू.पी.यू.ई.ए. इकोनामिक जर्नल अक्टूबर 2017।